Government Department to counter drinking water scarcity in these areas. The Collectors have also been directed to suspend recovery of land revenue and taccavi in the affected areas as per rules and procedures.

(f) Reply as at (c) and (d) above.

Financial Assistance to Panchayati Raj Institutions involved in Wasteland Development

4846. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government will extend financial assistance to Panchayati Raj institutions involved in Wasteland Development;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any such assistance was given to the States in 1994-95; and

(d) if so, the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) and (b) The ministry of Rural Areas & Employment have recently finalised Common Guidelines for Watershed Development of different types of lands including wastelands. Under this scheme the project would be implemented by the Project Implementation Agency. The role of the Agency will be to motivate the Gram Panchayats to pass the necessary resolution to public contributions, conduct participatory rural appraisal exercises to prepare the development plans for each watershed, undertake community organisation and training for village communities, provide technical guidance and provision of watershed development activities mainly project implementation, inspect and authenticate project accounts etcetera. Under the Guidelines the Gram Panchayats are also entitled to take on the responsibilities of implementing a cluster of watershed projects in the capacity of project implementation Agency.

(c) and (d) The Common Guidelines on Watershed Development were launched in October 1994 and would become operational from 1995-96. Hence no Panchayat has yet been given any financial assitance under these Guidelines.

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिये गये ऋण

4847. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता देने के लिए राजसहायता तथा ऋण उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक आधार पर धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 1992-93 और 1993-94 के दौरान वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से प्रत्येक वर्ष में आबंटित की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका था;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तव में कुल कितनी-कितनी राशि व्यय हुई;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन राजसहायताओं और ऋणों के परिणामस्वरूप कतिपय निर्धन परिवारों के जीवन-स्तर को भी बढ़ाया गया था, और

(च) यदि हां, तो उन परिवारों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें उक्त सहायता के परिणामस्वरूप मार्च, 1994 तक गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक